श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1763

सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946 (शक)

असम में चाय की खेती के लिए पारिश्रमिक और वित्तीय सहायता

1763. मोहम्मद रकीबुल हुसैन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अवगत है कि असम राज्य के बराक घाटी और असम घाटी के चाय बागान श्रमिकों को अलग-अलग वेतन मिलता है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या किन्हीं सरकारी योजनाओं द्वारा कृषि आधुनिकीकरण और उत्पादकता सुधार के लिए कम ब्याज पर ऋण प्रदान किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा चाय किसानों के, विशेषकर सुदूर क्षेत्रों में, विकास के लिए वित्तीय सहायता और संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का चाय श्रमिकों के दैनिक वेतन को बढ़ाकर 351 करने के अपने वादे को पूरा करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (च): बराक घाटी के वेतन पारंपरिक रूप से चाय के उत्पादन, गुणवत्ता और कीमत जैसे विभिन्न कारकों के कारण असम घाटी के वेतन की तुलना में कम दर पर रखे जाते हैं।

जमीनी स्तर पर बेहतर पहुंच के लिए चाय बागानों के क्षेत्रों में क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो लघु उपजकर्ताओं के साथ बातचीत करते हैं और दूरस्थ क्षेत्रों में योजनाओं का लाभ उठाने के लिए उन्हें सहयोग देते हैं। चाय बोर्ड की योजना के अंतर्गत सभी सेवाएं ऑनलाइन (सर्विस प्लस पोर्टल के माध्यम से) प्रदान की जा रही हैं और वित्तीय सहायता डीबीटी मोड में दी जाती है।

प्रमुख चाय उत्पादक राज्यों में वेतन का निर्धारण उत्पादक संघों, कामगार संघों और राज्य सरकारों के बीच हुए द्विपक्षीय/त्रिपक्षीय करार के अनुसार किया जाता है।

चाय बागान कामगारों के वेतन में वृद्धि करने के लिए न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड अधिसूचित किया गया है और बोर्ड के अंतर्गत एक सलाहकार समिति का भी गठन किया गया है।

*****